Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 12, December - 2023 Publication Date: 31/12/2023

DOIs:10.2018/SS/202312004 --:-- Research Paper / Article / Review

झारखंड में आदिवासी महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण के लिए सरकारी दृष्टिकोण

Dr. Rajendra Kumar Mahto[1]
Assistant Professor
Department Of Information Technology,
Dr Shayama Prasad Mukherjee University,
Ranchi
Email - rajendrabit57@gmail.com

Urmila Kumari[2]
Research Scholar
Department Of Khortha (TRL),
DSPMU, Ranchi
Email - urmilarkm94@gmail.com

शिक्षा :

शिक्षा सशक्तिकरण की प्रक्रियाओं को शुरू करने और बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा महिलाओं और हाशिए के समुदायों को अपनी स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है, उन्हें सूचना और संसाधनों तक अधिक पहुंच बनाने और भेदभाव के विभिन्न रूपों को चुनौती देने में सक्षम कर सकती है। शिक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में मदद करती है क्योंकि यह अधिक से अधिक न्यायसंगत भागीदारी की अनुमति देती है। शिक्षित या साक्षर होने से बड़ा आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान होता है। यह शक्ति की स्थिति से विकास प्रक्रियाओं और शासन की संस्थाओं के साथ जुड़ाव को सक्षम बनाता है। सामाजिक रूप से वंचित समुदायों की गरीब महिलाएं वास्तव में साक्षर नहीं हैं और इसलिए विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने के दौरान खुद को नुकसान में पाती हैं। वे पीआरआई में आरक्षण जैसे प्रगतिशील उपायों का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हैं। महिलाओं के लिए शिक्षा के दायरे से बाहर होने के कई नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक पहचाने जाते हैं, हालांकि, समस्या की अभिव्यक्ति बयानबाजी के स्तर पर बनी रहती है। उसके लिए हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो अच्छी गुणवत्ता की हो और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हो। लिंग के दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि शिक्षा और साक्षरता महिलाओं और लड़कियों को अपनी स्थितियों का गंभीर रूप से विश्लेषण करने, उनकी अधीनता के बारे में सवाल उठाने और उन्हें सूचित विकल्प बनाने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। यह सर्वविदित है कि स्कूली शिक्षा का संस्थान समाजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो वास्तव में पितृसत्ता और लैंगिक भेदभाव को चुनौती देने के बजाय वास्तव में मजबूत कर सकता है । यह इस संदर्भ में है कि शिक्षा की सामग्री और शिक्षाशास्त्र आलोचनात्मक विचार बन जाते हैं।

शैक्षिक नियोजन का ध्यान औपचारिक शिक्षा पर है लेकिन यह शैक्षिक प्रावधान का केवल एक आयाम है। खासकर वंचित महिलाओं की जरूरतों पर विचार करने और जब महिला सशक्तीकरण हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो औपचारिक प्रणाली के बाहर अच्छी तरह से विकसित और संरचित शैक्षिक हस्तक्षेप के बारे में सोचने की जरूरत है। क्षमता निर्माण के उपायों शैक्षिक और प्रक्रियाओं सीखने सार में हैं और इसलिए में निवेश किया जाना चाहिए, अच्छी तरह से डिजाइन और कल्पना के रूप में एक, निरंतर बजाय विज्ञापन हॉक प्रक्रिया। इस तरह के हस्तक्षेप को व्यापक रूप से आधारित और लचीला होना चाहिए और साक्षरता सहित कई विभिन्न आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिए ।

2. उभरते हुए निष्कर्ष :

प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और प्रतिधारण में लिंग अंतराल

प्रारंभिक शिक्षा भारत सरकार की प्रमुख नीति और कार्यक्रमगत चिंता के रूप में सामने आई है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। सर्वशिक्षा अभियान (SSA) या सभी के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ 2001 में शुरू किया गया था। SSA के भीतर विशिष्ट कार्यक्रम (प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय) शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में लड़कियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं । एक और मील का पत्थर योजना-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- शुरू की गई है। इस योजना का स्वागत

किया गया है क्योंकि यह गरीब और हाशिये के वर्गों से संबंधित लड़कियों और बच्चों के पोषण स्तर और स्कूल की भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है । हालांकि सुधार के बावजूद लिंग के संबंध में कई अंतराल हैं। अंतराल इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि रणनीतियों को घ को लक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि एसटी से संबंधित लड़कियां अभी भी पीछे हैं।

शेड्यूल ट्राइब्स (एसटी) समुदायों की लड़कियों और लड़कों की स्थिति सामान्य श्रेणी (सेलेक्ट एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, जीओआई 2003) **से कहीं अधिक खराब है** ।

- एससी लड़कियों के लिए जीईआर प्राथमिक स्तर पर 89.35 और मध्य विद्यालय स्तर पर 48.64 लड़कियां हैं।
- एसटी लड़कियों के लिए जीईआर प्राथमिक स्तर पर 92.25 और मध्य विद्यालय स्तर पर 40.78 लड़कियां हैं।

3. लैंगिक अंतर और महिला साक्षरता को कम प्राथमिकता :

2001 की जनगणना में साक्षरता दर (1991 में 52% से 2001 में 65% तक) में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 2001 में 14.8% की वृद्धि हुई, जबकि 1991 में 11.7% थी। निरक्षरों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि, साक्षरता लाभ के बावजूद, लिंग के संदर्भ में असमानताएं, अन्य सामाजिक श्रेणियां (जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति), ग्रामीण / शहरी स्थिति लगातार झलक रही हैं।

- पुरुष (75. 8%) और महिला (54,1%) की साक्षरता दर **22** % है।
- 2001 में, निरक्षरों के पास गिने **296 करोड़** है जिसमें से **190 मिलियन** थे *महिलाओं*/ 2003-04 में भारत में **34.6% दुनिया में गैर-साक्षर आबादी थी** ।
- **अधिकांश जिलों में** महिला साक्षरता दर **50% से कम है।**
- **66%** और क्रमशः 47.1%) और एसटी के लिए 24% (पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 59.2% और 34.8% थी)।

90 के दशक के मध्य तक साक्षरता के आसपास गति उत्पन्न हुई और यह साक्षरता दर में सुधार के परिणामस्वरूप हुआ । इस और इस तथ्य के बावजूद कि साक्षरता अभियानों ने बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं को संगठित किया, वयस्क साक्षरता और शिक्षा के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता कम हो गई। अधिकांश भाग के लिए कंटीन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम अशिक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं को आगे ले जाने में विफल रहा है। यह बहुत संभावना है कि भारत साक्षरता से संबंधित ईएफए और एमडीजी लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा (जैसा कि यूनेस्को ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2006 में बताया गया था)। वर्तमान स्थिति का अर्थ है कि स्वयं सहायता समूहों सहित महिलाओं के सामूहिकों के सशक्तिकरण की प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साक्षरता इनपुट प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। फील्ड की रिपोर्ट बताती है कि एसएचजी के भीतर साक्षरता के स्तर, नेतृत्व के अवसरों और क्रेडिट तक पहुंच के बीच एक उच्च संबंध है । और चूंकि सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शिक्षा सहसंबद्ध नेतृत्व है, इसलिए यह बेहतर बंद SHG सदस्यों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। इसी प्रकार, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में आने वाली महिलाओं, विशेषकर महिलाओं के पुरुष y खुद को नुकसान की स्थिति में पाते हैं। यह याद रखने की जरूरत है कि गरीब महिलाओं को साक्षरता और निरंतर शिक्षा प्रदान करने वाला यह एकमात्र कार्यक्रम है ।

चिंता का एक अन्य क्षेत्र वयस्क साक्षरता के लिए एक समकक्ष प्रणाली की कमी है। यह कमी उन महिलाओं और लड़कियों को रोकती है, जिन्होंने औपचारिक स्कूल प्रणाली के बाहर सीखा है, वास्तव में कई पदों (जैसे आशा, आईसीडीएस कार्यकर्ता) का लाभ उठाने के लिए जो विकास क्षेत्र के भीतर खुलते हैं। भरने के लिए सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से योग्य महिलाओं को खोजने की समस्या। ये स्थिति जारी है।

यह कई गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम महिलाओं और किशोरियों को चलाती है । एमएस द्वारा अपनाए गए नवीन दृष्टिकोणों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है।

मध्य अवधि के मूल्यांकन ने साक्षरता में व्यापक लिंग अंतर को कम करने और बड़े पैमाने पर सामुदायिक संगठनों को उत्प्रेरित करने में साक्षरता की भूमिका को कम करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित किया है ।

4. शिक्षा की सामग्री और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे :

यद्यपि लिंग और अन्य सामाजिक संबंधों को बदलने के लिए शिक्षा और कक्षा शिक्षण की सामग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है जो इसके हकदार हैं। पाठ्येतर लिंग-संवेदनशील बनाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन प्रारंभिक प्रयासों पर विचार किया जा सकता है क्योंकि वे बहुत हद तक रूढ़ियों को हटाने या दृश्यता बढ़ाने के स्तर पर बने हुए हैं और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में लिंग को नहीं देखा है। हाशिए के समुदायों के प्रतिनिधित्व से संबंधित समस्याएं मौजूद हैं और मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से इन समुदायों के अलगाव की गहरी भावना और बच्चों को छोड़ने का एक कारण है। कामुकता को शैक्षिक सामग्री में समस्याग्रस्त तरीके से संबोधित किया जाता है। कक्षाओं को उन स्थानों में बदलना होगा जो लड़कियों को गंभीर रूप से सोचने में मदद कर सकें। पहचान आधारित पूर्वाग्रहों पर आधारित भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर नजर रखने और रोकने की जरूरत है। शारीरिक दंड, जो कि व्यापक प्रसार है, की जाँच की जानी चाहिए। इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। लिंग अभिविन्यास सत्रों की वर्तमान रणनीति तदर्थ और अप्रभावी साबित हुई है। नियमित सेवा और पूर्व-सेवा पाठ्यक्रम के शिक्षकों के भीतर लिंग और सामाजिक इक्विटी चिंताओं को शामिल करने की आवश्यकता है।

5. महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शिक्षा पर प्रभाव :

शैक्षणिक संस्थानों के भीतर लड़कियों और युवतियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हिंसा व्यापक रूप से कम लेकिन रिपोर्ट की जाती है। हालांकि कोई डेटा (या डेटा इकट्ठा करने के लिए व्यवस्थित तंत्र) नहीं है जो समस्या की सीमा को इंगित करता है। जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और तंत्र स्थापित किया है, कई शिक्षण संस्थानों में अभी भी नीतियां नहीं हैं। यद्यपि तकनीकी रूप से दिशानिर्देशों को स्कूलों को कवर करना चाहिए, लेकिन स्कूलों में दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, जहां यौन उत्पीड़न काफी आम है, लेकिन शायद ही कभी रिपोर्ट किया जाता है। केवल एक मीडिया के पास इस तरह की जानकारी के लिए भरोसा करने के लिए है।

एक और क्षेत्र जिसे बहुत अधिक ध्यान नहीं मिला है, वह है शिक्षा पर संघर्ष और सांप्रदायिक और सांप्रदायिक हिंसा का प्रभाव । सांप्रदायिक और सांप्रदायिक हिंसा और दीर्घकालिक संघर्ष लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं झारखंड 1992। अस्थिर परिस्थितियों में लड़कियों को स्कूलों से दूर रखा जाता है। दंगा प्रभावितों में से कई बुनियादी सुविधाओं तक कम पहुंच वाले प्रवासियों का जीवन जी रहे हैं ।

भारत के कुछ हिस्सों में, जैसे कि झारखंड राज्य कई वर्षों से संघर्ष का सामना कर रहा है , जमीनी स्तर की स्थिति बताती है कि लंबे समय तक हिंसा ने वहां की शिक्षा प्रणालियों और महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों को विभिन्न तरीकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। डर, अत्यधिक असुरक्षा, प्रतिबंधित गतिशीलता, विस्थापन, प्रवास या आर्थिक मजबूरियों के कारण लड़कियों की ड्रॉपआउट दर अधिक है। लड़कियों के लिए स्कूल की भागीदारी और शिक्षा की गुणवत्ता महिलाओं की कामुकता और गतिशीलता को नियंत्रित करने के उपायों से प्रभावित होती है , जैसे कि डिकेट एक ड्रेस कोड लागू करते हैं, धार्मिक निकायों द्वारा, आतंकवादी या अलगाववादी समूह असामान्य नहीं हैं। घबराहट विकारों में खतरनाक वृद्धि होती है।

ऐसी स्थितियों में स्कूली शिक्षा और अन्य शैक्षिक हस्तक्षेप सामान्य स्थिति के बारे में बता सकते हैं और मुख्यधारा से अलगाव को रोक सकते हैं। शिक्षा, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों पर संघर्ष के प्रभाव को समझने और निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किए गए हैं। हिंसा और संघर्ष के प्रभाव का जवाब देने के लिए कोई नीतिगत दिशानिर्देश नहीं हैं। ऐसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं । लिंग के नजरिए से प्रावधान करने वाली शिक्षा को आंतरिक विस्थापन और राहत और पुनर्वास पर किसी भी नीति में एक जगह मिलनी चाहिए ।

6. सर्व शिक्षा अभियान :

- एसएसए के माध्यम से ग्यारहवीं योजना के अनुसार विशिष्ट समूहों, संदर्भों और स्थानों और डिजाइन कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए। समूहों तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन एसएसए के भीतर विशेष परियोजनाओं के माध्यम से पहुंचना चाहिए।

- शैक्षिक डेटा को लिंग असहमति होना चाहिए लेकिन अन्य सामाजिक समूहों के संदर्भ में भी एकत्र किया जाना चाहिए। योजना और कार्यक्रम की डिजाइन प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सामाजिक समूहों की व्यवस्थित मैपिंग की जानी चाहिए।
- एसटी लड़कियों और महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए, नीतिगत उपायों और संसाधन आवंटन द्वारा समर्थित विशिष्ट कार्यक्रमों को तत्काल आधार पर लागू करने की आवश्यकता है।
    - एसटी बालिका शिक्षा पर एक उप योजना का गठन किया जाना चाहिए, जो एक राष्ट्रीय कार्य बल के रूप में कार्य कर सकती है , जिसे लागू किया जाना चाहिए।
    - एक उच्च अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में औपचारिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हालाँकि एक ही समय में समुदाय के नेताओं को अपनी बालिकाओं को स्कूलों में जाने और उन्हें स्कूल प्रणाली में बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के ध्यान के बाद उच्च ड्रॉप आउट दरों से बचने के लिए एसएसए को माध्यमिक विद्यालय स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। अवसंरचना संबंधी मुद्दों जैसे स्वच्छता आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मौजूदा योजनाओं की समीक्षा के बाद प्रोत्साहन योजनाओं पर विचार किया जा सकता है।
- एनपीईजीईएल और केजीवीबी जैसे कार्यक्रम जो लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उन्हें निरंतर और मजबूत किया जाना चाहिए।
- महिला शिक्षकों को काम पर रखने की नीति जारी रखी जानी चाहिए। एसटी जैसे सामाजिक वंचित समूहों से महिला शिक्षकों के पूल को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

7. वयस्क साक्षरता और शिक्षा :

- महिला सशक्तीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को देखते हुए, स्व-सहायता समूहों सहित महिलाओं के सामूहिक और ईएफए तक पहुंचने में इसकी महत्वपूर्णता वयस्क साक्षरता के प्रति प्रतिबद्धता को लक्षित करती है और शिक्षा को फिर से व्यक्त किया जाना चाहिए और पर्याप्त संसाधनों द्वारा समर्थित होना चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। सीई कार्यक्रम को महिलाओं के समूहों और अन्य नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी के साथ डिजाइन किए गए नए कार्यक्रमों को नया रूप दिया जाना चाहिए। जैसा कि हाशिए के समुदायों की महिलाओं की साक्षरता दर बहुत खराब है, ऐसे कार्यक्रमों को विभिन्न समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहिए। कार्यक्रम सामग्री को आजीविका और अन्य अस्तित्व के मुद्दों और संगठन के निर्माण के साथ साक्षरता को जोड़ना चाहिए।
- वयस्क शिक्षार्थियों के लिए समतुल्यता कार्यक्रम और प्रमाणन प्रणाली निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वे खुलने वाले विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकें। यह ओपन लर्निंग मोड के माध्यम से और NIOS के जनादेश का विस्तार करके किया जा सकता है।
- एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम जिसमें लिंग, कानूनी साक्षरता, आजीविका और साक्षरता शामिल है, को डिजाइन किया जाना चाहिए और एसएचजी के माध्यम से नेतृत्व की स्थिति में उभरने वाली महिलाओं के लिए इसके लेनदेन के लिए एक तंत्र रखा जाना चाहिए।

8. शिक्षा और प्रशिक्षण की सामग्री और गुणवत्ता :

- शिक्षाविदों और चिकित्सकों की भागीदारी के साथ पाठ्यपुस्तक सुधार प्रक्रियाओं को जारी रखा जाना चाहिए। लिंग को एक ऐड-ऑन के रूप में नहीं बल्कि सभी विषयों में एकीकृत करने की आवश्यकता है और इसे राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण आयोजन सिद्धांत होना चाहिए। कामुकता के मुद्दों को बच्चों को जानकारी प्रदान करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है, उन्हें सूचित विकल्प बनाने के लिए सक्षम करें, उन्हें कामुकता और लिंग की अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूक करें और उल्लंघन से निपटने के लिए उन्हें लैस करें। त्वरित शिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक नया पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है।

- शिक्षक प्रशिक्षण और छात्र शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम (डाइट) में लैंगिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल शामिल होना चाहिए। लिंग को नियमित और पूर्व सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भीतर एक विषय बनना चाहिए।

9. उच्च और पेशेवर प्रशिक्षण :

जनजातियों की महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए कम उपयोग। वर्तमान प्रयासों की समीक्षा की जानी चाहिए और उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में इन समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करनी चाहिए।

पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में महिलाओं और लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के लिए रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए। प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को समयबद्ध योजना के साथ आने के लिए संपर्क किया जाना चाहिए।

10. VAW और शिक्षा :

स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न के लिए दिशानिर्देश (उच्च प्राथमिक ऊपर की ओर रखा जाना चाहिए) और निगरानी की जाती है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ यौन और अन्य प्रकार की हिंसा पर जागरूकता शामिल होनी चाहिए। इस मुद्दे को स्कूली पाठ्यक्रम में संवेदनशील रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इन मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक संस्थानों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। वर्तमान में कोई नीतिगत ढाँचा नहीं है जो संघर्ष की विभिन्न स्थितियों से उभरने वाली विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम और नीतिगत दिशानिर्देश विशेष रूप से आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किए जाने चाहिए , विशेष रूप से मुख्यधारा से भय और असुरक्षा और अलगाव की भावनाओं को दूर करना। ऐसी स्थितियों में महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि यह एक शोधित क्षेत्र है, कुछ अध्ययनों को कमीशन किया जा सकता है।

सुनिश्चित करें कि जीडीपी का 6% सभी स्तरों पर और उच्चतर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशिष्ट आवंटन के साथ सभी प्रकार की शिक्षा में निवेश किया जाता है ।

जेंडर बजटिंग मैकेनिज्म को लागू किया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए और नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए । व्यय और प्रोग्रामिंग दोनों के संदर्भ में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवंटित धन की ट्रैकिंग होनी चाहिए ।

11. स्वास्थ्य और पोषण :

अपने जीवन-चक्र में एक महिला अपने स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों के मामले में कई चुनौतियों से गुजरती है क्योंकि ये न केवल स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच पर निर्भर हैं, बल्कि समाज में उनकी स्थिति के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं जो उन्हें लगातार इससे वंचित करती हैं। इन आवश्यकताओं को उचित रूप से संबोधित किया जाना। गरीबी और आर्थिक निर्भरता, लैंगिक पक्षपात और भेदभाव, यौन और प्रजनन पहलुओं पर सीमित स्वतंत्रता और निर्णय लेने की कमी का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, स्वास्थ्य के कुछ निर्धारक हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं जैसे:

- सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता
- सुरक्षित और पर्याप्त पोषण
- पर्याप्त आवास
- स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण
- स्वास्थ्य साक्षरता, शिक्षा और सूचना
- लैंगिक समानता

महिला स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के महत्व को भारत सरकार द्वारा महसूस किया गया है। कई हस्तक्षेप किए गए हैं और महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं लेकिन विकास की प्रमुख चुनौतियों को अभी भी प्रतिकूल लिंग-विशिष्ट स्वास्थ्य संकेतकों (मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात, कुपोषण, एनीमिया आदि) के संदर्भ में संबोधित किया जाना बाकी है। यह आगे 2011 की जनगणना के निष्कर्षों से प्रमाणित होता है, जहां बाल लिंग अनुपात

(0-6 वर्ष) में बिगड़ती प्रवृत्ति, उच्च मातृ और बाल मृत्यु दर और रुग्णता एक चुनौती बना रही है। NFHS-3 के सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि भारत में हर तीसरी महिला अल्पपोषित है (33.0 प्रतिशत की कम बॉडी मास इंडेक्स है) और हर दूसरी महिला एनीमिक है (15.249 के आयु वर्ग में 56.2 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं)।

12. नीतियाँ :

भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न नीतियां निर्धारित की गई हैं। ये नीतियां उस आधार पर होंगी जिस पर मिशन अभिसरण प्रयासों की निगरानी करेगा और विभिन्न परिणाम संकेतकों की उपलब्धि की सुविधा प्रदान करेगा जैसे कि मातृ मृत्यु दर में कमी, 0-6 आयु वर्ग के लिए संतुलित बाल लिंग-अनुपात, टीकाकरण के पूर्ण पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करना, पोषण में सुधार। माँ और शिशुओं की स्थिति, और विवाह की उम्र और पहली गर्भावस्था में वृद्धि।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 नीति गरीबों के स्वास्थ्य, और समर्पित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक वर्ग और सामाजिक संबंधित पर भर केंद्रित है , आर्थिक दस्तावेज़ पूरे समुदायों के स्वास्थ्य के प्रमुख निर्धारक के रूप में महिलाओं के स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करता है। यह भी स्वीकार करता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी महिलाओं को पर्याप्त पहुंच प्राप्त करने से रोकते हैं। नीति महिलाओं की देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की आवश्यकता का समर्थन करती है। नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में स्टाफिंग की समीक्षा करने की आवश्यकता की भी वकालत करती है, ताकि यह महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन सके। नीति समुदाय के समग्र स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने में सशक्त महिलाओं की उत्प्रेरक भूमिका को स्वीकार करती है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000- नीति प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाते हुए, स्वैच्छिक और सूचित पसंद और नागरिकों की सहमति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, और परिवार नियोजन सेवाओं को संचालित करने में लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण को जारी रखती है। एनपीपी को भारत के लोगों की जरूरत है, और 2010 तक शुद्ध प्रतिस्थापन स्तर (टीएफआर) प्राप्त करने के लिए । यह एक व्यापक पैकेज के आउटरीच और कवरेज में वृद्धि के साथ-साथ बाल अस्तित्व, मातृ स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक के मुद्दों को एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता पर आधारित है । सरकार, उद्योग और स्वैच्छिक गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रजनन और बाल हीथ सेवाओं में भागीदारी में काम करना।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति -२००० और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति -२००२ के अंतर्गत आने वाली सामान्य विशेषताएं , संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित हैं; एचआईवी / एड्स संक्रमण की रोकथाम को प्राथमिकता देना ; सभी प्रमुख रोके जाने वाले रोगों के खिलाफ बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण ; बुनियादी और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, और बुनियादी ढांचे के पूरक के लिए असमान जरूरतों को संबोधित करना ।
- राष्ट्रीय पोषण नीति 1993- इस नीति की शुरुआत कम पोषण की समस्या से निपटने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष (अल्पावधि) हस्तक्षेपों का उपयोग करके बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं का उचित पोषण सुनिश्चित करना, खाद्य दुर्ग, कम लागत वाले पौष्टिक भोजन का प्रावधान करना और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मुकाबला करना और कमजोर समूहों में कमी को दूर करना है। अप्रत्यक्ष (दीर्घकालिक) हस्तक्षेप में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, आहार वितरण में सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पोषण शिक्षा, भूमि सुधार, सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार के माध्यम से क्रय शक्ति शामिल है ।

अनुसंधान के क्षेत्र में झारखंड सरकार ने ग्रामीण स्तर पर पीएचसी (प्राथमिक केंद्र) स्थापित किया है। गंडकी, चिंगगढ़ और दुलमी गाँव में कुल छह आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जिन्हें SAHIYA कहा जाता है। समाज में महिलाओं की स्थिति बदली है। वे परिवार में एक महान भूमिका निभा रहे हैं। अधिकांश घरेलू कामों में आदिवासी महिलाएं निर्णय ले रही हैं जैसे बच्चों के भवन विवाह का निर्माण आदि। वे परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। वे लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वे लड़की को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि लड़की शिक्षित है तो लड़की की शादी करना आसान है। वे समाज में निर्णय लेने में भाग ले रहे हैं। यदि कोई समस्या समाज में व्याप्त है। महिलाओं ने सामूहिक रूप से कार्रवाई की और समस्याओं को हल करने के लिए एक जगह पर बैठे। उदाहरण के लिए, चंगराह गांव में एक आदिवासी और

गैर आदिवासी की लड़की के बीच प्रेम संबंध की समस्या सामने आती है। इस मामले में आदिवासी महिलाएँ जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, ने कार्रवाई की और समाज में उनका विवाह किया।

सरकार कुछ सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रहा है, एमएनईजीए, आईसीडीएस, MUKHYAMANTRI KANYADAN YOJNA, SGSY और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि हैं। आंगनवाड़ी केंद्र गांवों में चल रहे हैं । आंगनवाड़ी केंद्र आदिवासी महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। इन आगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को स्कूल जाने से पहले शिक्षित किया जा रहा है। आदिवासी महिलाओं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ब्लॉक करने के लिए जाना ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के खिलाफ लड़ाई के लिए गांव में आदिवासी महिलाओं ने संगठित किया। उन्होंने शराबी और तार निर्माण के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

ग्रंथ सूची :

1. भट्ट, इला 1989. "सशक्तिकरण की ओर।" विश्व विकास 17 (7): 1059-1065।
2. कबीर, नैला। 2001. "महिला सशक्तिकरण के मापन पर विचार" महिला सशक्तिकरण पर *चर्चा करते हुए।*
3. मैनसन, करेन। 1986. "महिलाओं की स्थिति: जनसांख्यिकीय अध्ययन में वैचारिक और पद्धतिगत मुद्दे।" *समाजशास्त्रीय फोरम 1 (2): 284-300 /*
4. मेहरा, रेखा। दिनांक। "महिला, सशक्तीकरण और आर्थिक विकास।"
5. सिंह, ए। के। 1998 वन और जनजातीय भारत में; शास्त्रीय प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली।
6. सिंह, ए। के। 1994 ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ बिहार, ए फंक्शनल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
7. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)। 1994. महिला समानता और सशक्तीकरण ढांचा। Www.unicef.org/programme/gpp/policy/empower.html पर ऑनलाइन उपलब्ध ।
8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)। 1995. *मानव विकास रिपोर्ट 1995:* लिंग और विकास। न्यूयॉर्क और ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।